

मुकदमों का विवरण

जोसेफ

बनाम

केरल और ओआरएस का राज्य।

(रिट याचिका (आपराधिक) सं.520 2022 का) 21 सितंबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:क्या याची के नेतृत्व में राज्य सरकार को उचित निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका में उसे समय से पहले रिहा करने की मांग की गई है, जो 26 साल से अधिक समय से हिरासत-वास्तविक कारावास में है, और दंडनीय अपराध के लिए अर्जित 8 साल से अधिक की छूट सहित 35 साल से अधिक की सजा काट चुका है।302 और आई. पी. सी. 392 की अनुमति दी जानी चाहिए।

समयपूर्व रिहाई-दोषी ने वास्तविक कारावास में 26 साल से अधिक की सेवा की और 35 साल की सजा काट ली, जिसमें 8 साल की छूट भी शामिल है।302 और 392-राज्य सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए तीन बार खारिज किया गया मामला-लिखित याचिका जिसमें राज्य सरकार को समय से पहले रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है:

आयोजित किया गया:व्यावहारिक दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्तिगत दोषी की सुधारात्मक क्षमता को नजरअंदाज करने का वास्तविक खतरा हो सकता है-दोषियों के प्रकारों को, एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, उनके द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर, न्यायसंगत ठहराया जा सकता है, हालांकि, भारत में जेल कानूनों को कला के सहपठित पढ़ा जाता है।72 और 161 एक मजबूत अंतर्निहित सुधारात्मक उद्देश्य को समाहित करते हैं-दिशानिर्देशों का आग्रह, और जेल के अच्छे व्यवहार के वास्तविक प्रभाव पर विचार करने से इनकार, और अन्य प्रासंगिक कारकों के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है-उन कैदियों को समय से पहले रिहाई की राहत को छोड़कर, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कारावास की सेवा की है, न केवल उनकी भावना को कुचलता है, और निराशा पैदा करता है, बल्कि यह समाज के कठोर और अक्षम्य होने के संकल्प को दर्शाता है-अच्छे आचरण के लिए एक कैदी को पुरस्कृत करने का विचार पूरी तरह से नकार दिया जाता है -2014 के नियम 506 का आर. 376

505

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यह निर्धारित करता है कि कैदियों को जेल में शांति और अच्छा व्यवहार रखने के लिए छूट दी जाएगी-याची को, जो पहले ही 26 साल से अधिक की कैद और 35 साल से अधिक की सजा से गुजर चुका है, फिर से सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए निर्देशित करना, और उसके बाद, समय से पहले रिहाई के लिए राज्य सरकार, क्रूर होगी-याची ने 8 साल से अधिक की छूट अर्जित की है, इस प्रकार जेल में अच्छा आचरण प्रदर्शित करता है-जेल सलाहकार बोर्ड की चर्चा भी सकारात्मक है और यह दर्शाता है कि वह एक सुधार कैदी है-इस प्रकार, न्याय के हित में, याची को रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है-केरल जेल नियम, 1958-केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014-आर 462 से 468।[पारस 33-35]

छूट-छूट का अनुदान-इसका दायरा:

आयोजित किया गया: एक कार्यकारी नीति के माध्यम से छूट देने के दायरे से कुछ व्यक्तियों का खाली स्थान पर बहिष्कार मनमाना है और आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से चलने वाले सुधार के आदर्शों के खिलाफ है-दंडात्मक लक्ष्य प्रतिशोध के बजाय सुधार और पुनर्वास का है- इस तरह के कार्यकारी निर्देश/दिशानिर्देश को लागू करने का प्रभाव यह होगा कि एक दीर्घकालिक दोषी द्वारा की गई कोई भी प्रगति उन्हें निराशाजनक महसूस कराएगी, और उन्हें अनिश्चित काल के लिए कारावास की सजा दी जाएगी।[पैरा 28]

छूट-छूट नीति-निम्नलिखित का अनुप्रयोग:

आयोजित किया गया: दोषसिद्धि की तिथि पर प्रचलित माफी नीति, किसी दिए गए मामले में लागू की जानी है, और यदि विचार के दिन अधिक उदार नीति मौजूद है, तो बाद वाली नीति लागू होगी।[पैरा 19]

प्रशासनिक कानून-पूर्ण कानून या वैधानिक नियमों द्वारा व्यापक रूप से प्रदत्त विवेक:

आयोजित किया गया: इसे हल्के में नहीं बांधा जा सकता है।[पैरा 29]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरियाणा राज्य बनाम जगदीश [2010] 3 एस. सी. आर. 716; मारू राम बनाम भारत संघ [1981] 1 एस. सी. आर. 1196; जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बनाम सुभाष चंद्र यादव [1988] 3 एस. सी. आर. 62; हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह

[2007] 11 एस. सी. आर. 932; राज्य बनाम एच. नीलोफर निशा (2020) 14 एस. सी. सी. 161; [2020] 1

एस. सी. आर. 456; रामदास अठावले बनाम भारत संघ [2010] 3 एस. सी. आर. 1059; संघ 507

भारत बनाम वी. श्रीहरण [2015] 14 एससीआर 613; स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य [2008] 11 एससीआर 93; मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह [1976] सप।1 एस. सी. आर. 552; राजन बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग [2019] 6 एस. सी. आर. 1035; हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार (2021) 9 एस. सी. सी. 292; राजो बनाम बिहार राज्य निर्णय

लिखित याचिका (सी. आर. एल.) में दिनांक 25.08.2023 नं. 252/2023; हरियाणा राज्य बनाम

मोहिंदर सिंह [2000] 1 एससीआर 698; संगीत बनाम हरियाणा राज्य [2012] 13 एससीआर 85; राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2022] 4 एससीआर 1103; यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्न बनाम मोहम्मद।इस्माइल और ओरस। [1991] 2 एससीआर 274; अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे रे. बोर्ड और ओआरएस. वी.के. श्याम कुमार और ओआरएस। [2010] 6 एस. सी. आर. 291-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) No.520

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

एडोल्फ मैथ्यू, संजय जैन, अधिवक्तागण याची के लिए।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, सुभाष चंद्रन के. आर., श्रीमती अश्ली हर्षद, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. याची , जो वर्तमान में 1996 में किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, भारतीय न्यायालय संहिता की धारा 302 और 392 (इसके बाद "आई. पी. सी.") के तहत न्यायालयनीय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार को लागू करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाता है। वह 26 साल से अधिक समय से हिरासत (यानी वास्तविक कारावास) में रहने और 35 साल से अधिक की सजा (अर्जित 8 साल से अधिक की छूट सहित) काटने के बाद राज्य सरकार को समय से पहले रिहा करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग करता है।

जोसफ बनाम केरल राज्य 508 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

तथ्य और पृष्ठभूमि

2. यह आरोप लगाया गया था कि 16.09.1994 पर, याची अपनी साली (मृतक पीड़ित) के कार्यस्थल पर गया था, और इस झूठे बहाने से कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे कॉन्वेंट के प्रभारी की अनुमति से ले गया जहाँ वह काम करती थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उसने उसे रेलवे लाइन के साथ और एक सुनसान जगह पर टहलाया, कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और उसके पहने हुए गहने लूट लिए, इससे पहले कि वह उसे पटरियों पर रख दे ताकि वह एक चलती ट्रेन से बह जाए।

3. याची को मामले के संबंध में 09.10.1994 पर गिरफ्तार किया गया था और तब तक हिरासत में रहा जब तक कि निचली विचारण न्यायालय 1 ने उसे 23.03.1996 पर सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। उच्च न्यायालय 2 ने बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया और याची को आई. पी. सी. की धारा 302, 376 और 392 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपने दिनांक 1 के फैसले द्वारा दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने उन्हें आई. पी. सी. की धारा 376 और 392 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक मामले में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो एक साथ चलने वाले थे। हालाँकि, इस न्यायालय 3 ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया और केवल आई. पी. सी. की धारा 302 और 392 के तहत दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार किया।

4. इस न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी-राज्य ने अपनी सजा की अवधि की गणना, छूट के लिए उनकी याचिका की स्थिति, साथ ही राज्य की विभिन्न माफी नीतियों (समय-समय पर संशोधित) का नेतृत्व करने का संकेत देते हुए एक हलफनामा दायर किया। याची ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से पहले एक विचाराधीन के रूप में 1 वर्ष 5 महीने और 10 दिनों की हिरासत पूरी की। उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्होंने 28.01.1998 पर सजा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद हिरासत में रहे। 13.08.2010 पर, उन्होंने 14 साल का वास्तविक कारावास (एक विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए गए समय सहित) पूरा किया। और 13.08.2016 पर, उन्होंने वास्तविक कारावास के 20 साल पूरे किए। उसकी रिट याचिका में पेश अभिरक्षा प्रमाण पत्र में कहा गया है कि उसने 25 साल 9 महीने और 26 दिनों का वास्तविक कारावास 07.06.2022 पर पूरा किया (यानी, उसने 25 साल वास्तविक रूप से पूरे किए)।

1 सत्र न्यायालय, त्रिशूर द्वारा एस. सी. सं. 73/1995 में पारित दिनांक 23.03.1996 के निर्णय द्वारा।

2 केरल उच्च न्यायालय द्वारा सी. आर. एल. में पारित दिनांक 06.01.1998 के निर्णय द्वारा। ए. नहीं. 511/1996।

3 इस न्यायालय द्वारा सीआरएल में पारित दिनांक 27.04.2000 के निर्णय द्वारा। ए. नहीं. 656/1998।

13.08.2021) पर कारावास।हालाँकि, राज्य के जवाबी आरोप के संदर्भ में, 31.01.2023 के अनुसार, उन्होंने 25 साल 10 महीने 3 दिन का वास्तविक कारावास पूरा किया और 8 साल 4 महीने और 16 दिन की छूट अर्जित की।अंकगणितीय विसंगतियों के बावजूद, यह विवादित नहीं है कि उन्होंने वास्तविक कारावास के 26 साल पूरे कर लिए हैं।

5. सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता के मामले पर सलाहकार समिति/जेल सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रचलित नियम 4 के तहत नौ मौकों पर विचार किया गया था, जिनमें से तीन बार बोर्ड ने उनकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी।हालाँकि, राज्य सरकार ने तीनों मौकों पर उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।इस न्यायालय के एक निर्देश के अनुसरण में, राज्य ने बैठक के प्रत्येक कार्यवृत्त/सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें याची से संबंधित सिफारिशें (सकारात्मक और नकारात्मक) हैं, और राज्य द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश तीन अवसरों पर जिसमें बोर्ड ने रिहाई की सिफारिश की थी।इनका सारांश नीचे दिया गया है:

सलाहकार समिति/जेल सलाहकार बोर्ड	
लागू तिथि और सांविधिक प्रावधान /नियम	याचिका कर्ता के मामले और तर्क पर विचार
10.08. 2011 [1958 नियम]	याचिका कर्ता का मामला सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया क्योंकि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला था।
27.08. 2013 [1958	पुलिस रिपोर्ट और कार्रवाई

नियम]	करने के तरीके के आधार पर, तीन आधिकारिक सदस्यों ने सिफारिश का विरोध किया, जबकि तीन गैर-आधिकारिक सदस्यों ने रिहाई की सिफारिश की। समिति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
30.06. 2014 [1958 और 2014 दोनों नियम]	अलग-अलग शीर्षक के तहत सूचीबद्ध 'उन कैदियों के मामले जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन वे पूर्व मध्यस्थ नहीं हैं

और
इस
प्रकार
सरकारी
निर्देशों
के दायरे
में आते
हैं।
जिला
परिवीक्ष
ा
अधिका
री ने
रिहाई
की
सिफारि
श की,
जबकि
पुलिस
ने
विरोध
किया।
दर्ज
किया
कि वह
मेहनती,
अनुशा
सित
और
सुधार है
और
इसलिए

याचिका
कर्ता के
मामले
को
अगली
बैठक
के लिए
स्थगित
कर
दिया
गया था
क्योंकि
उसने

17
साल से
अधिक
का
कारावा
स पूरा
कर
लिया

4 केरल कारागार नियम, 1958 (इसके बाद '1958 नियम') और केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014 (इसके बाद '2014 नियम')।

29.09.2015 [2014 नियम]	विचार की अंतिम तिथि के समान टिप्पणियां/निष्कर्ष; परिवीक्षा अधिकारी और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता के मामले पर सर्वसम्मति से नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया और मामले को नवंबर 2015 तक विचार के लिए स्थगित कर दिया गया।
08.01.2016 [2014 नियम]	याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट में रिहाई की सिफारिश नहीं की गई थी।
10.01.2017 [2014 नियम]	पुलिस रिपोर्ट ने रिहाई की सिफारिश नहीं की, जबकि क्रमशः परिवीक्षा अधिकारी और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट ने रिहाई का समर्थन किया। पुलिस रिपोर्ट, लगाए गए आरोपों और जेल के अंदर और बाहर उनके जीवन की विस्तृत

	चर्चा के बाद परिवीक्षा अधिकारी और गैर- आधिकारिक सदस्यों ने रिहाई का समर्थन किया। इसके बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता के मामले को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की।
13.08.2019 [2014 नियम]	जिला परिवीक्षा अधिकारी ने समय से पहले रिहाई की सिफारिश की, जबकि पुलिस रिपोर्ट ने फिर से रिहाई के खिलाफ सिफारिश की। पैरोल पर उनके जीवन, जेल में चरित्र और अवधि को ध्यान में रखते हुए, मामले को अगली बैठक में विचार के लिए स्थगित कर दिया गया था।
26.02.2020 [2014 नियम]	लंबी अवधि के कारावास, दोषी की उम्र, जेल में चरित्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के मामले में सर्वसम्मति से रिहाई की सिफारिश की गई।
07.03.2022 [2014 नियम]	याचिकाकर्ता के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड के जिला न्यायाधीश ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जिन व्यक्तियों ने महिलाओं और

	बच्चों की हत्या की थी और एन. डी. पी. एस. के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को रिहा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सभापति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार के साथ हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, एक गैर-आधिकारिक सदस्य ने बताया कि उन्होंने 24 साल से अधिक वास्तविक कारावास का सामना किया है, बोर्ड द्वारा 5 बार विचार किया गया है और 2 बार रिहाई के लिए सिफारिश की गई है, और मानवीय आधार पर रिहाई के लिए विशेष विचार किया जा सकता है। उनकी उम्र और लंबे कारावास को देखते हुए, याचिकाकर्ता के मामले को सर्वसम्मति से समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की गई थी।
राज्य सरकार का निर्णय	
निर्णय की तिथि	याची से संबंधित सरकार का निर्णय

06.07.2019	सलाहकार बोर्ड की तारीख 10.01.2017 की सिफारिश के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले (अन्य तीन दोषियों के साथ) को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था।
22.04.2021	सलाहकार बोर्ड की तारीख 26.02.2020 की सिफारिश के अनुसार, रिहाई के लिए अनुशंसित सभी 20 व्यक्तियों से संबंधित मामला, आगे की कार्रवाई के लिए वापस कर दिया गया।
01.09.2022	सलाहकार बोर्ड की तारीख 07.03.2022 की सिफारिश के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले (7 अन्य लोगों के साथ) को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था।

6. राज्य ने अपने जवाबी बयान में अपनी स्थिति स्पष्ट की-कि याची को 9 बार समय से पहले रिहा करने के लिए विचार किया गया है, लेकिन उसका मामला बार-बार खारिज किया गया है क्योंकि:

“कैदियों की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, सरकार द्वारा अब लगातार यह रुख अपनाया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों की हत्या में शामिल व्यक्तियों और पॉक्सो मामलों से संबंधित अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को समय से पहले रिहाई नहीं दी

जाएगी।चूंकि याची एक महिला की हत्या में शामिल था, इसलिए उसकी समय से पहले रिहाई को सरकार ने उपरोक्त रुख के अनुसार खारिज कर दिया था।”

(जोर दिया गया) इसके अलावा, 2020 में, समय से पहले रिहाई देने के संबंध में कैदियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक विशेष रूप से गठित समिति 5 द्वारा सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए जाने थे।इस समिति ने अपने-अपने मामलों का आकलन करने के बाद 67 दोषियों (जिन्हें पहले किसी भी कारण से खारिज कर दिया गया था) को समय से पहले रिहा करने का प्रस्ताव रखा।राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 20.04.2022 की कार्यवाही के माध्यम से, कुछ दोषियों को बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो इसमें शामिल थे:सबसे क्रूर हत्या, महिला और बच्चों की हत्या, या बलात्कार के साथ हत्या, और मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे लोग, जिनके रिश्तेदार उन्हें स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे।ये प्रतिबंध, अन्य अधिक विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ,

5 इस समिति में अध्यक्ष के रूप में गृह और सतर्कता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कानून सचिव और सदस्यों के रूप में प्रिओं और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक शामिल थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

केरल राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश 6 दिनांक 04.06.2022 में शामिल किया गया है।

7. 01.09.2022 पर, राज्य सरकार ने तीसरी बार याची को रिहा करने की सलाहकार बोर्ड की सिफारिश को खारिज कर दिया।पीड़ित, याची ने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

दलों की दलीलें

8. याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री एडॉल्फ मैथ्यू ने समय से पहले रिहाई के लिए उनकी याचिका को बार-बार खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी।यह इंगित किया गया था कि दोषसिद्धि की तारीख पर प्रचलित माफी नीति को लागू करना होगा।1958 के नियमों के नियम 545 ए की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था जिसमें कहा गया है कि रिहाई पर 14 साल के बाद विचार किया जा सकता है; 1958 के नियमों के नियम 216 (1), 244 (2) और 299 (सी) में कहा गया है कि कैदी को 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा किया जाएगा; और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) की सिफारिशें जो 25 साल की सजा के बाद अनिवार्य रिहाई निर्धारित करती हैं।इसके अलावा, नए जेल नियम, 2014 के नियम 377 के संदर्भ में भी, याची 20 साल के बाद रिहा होने का हकदार है।यह तर्क दिया गया कि चूंकि याची ने न केवल 14 वर्ष या 20 वर्ष पूरे किए हैं, बल्कि 25 वर्ष का

वास्तविक कारावास भी पूरा किया है, इस समय-चाहे कोई भी नियम लागू हों, उसे स्थायी रूप से कैद में रखना स्पष्ट रूप से अवैध था।

9. श्री मैथ्यू ने राज्य की दिनांकित 14.06.2022 नीति (और राज्य के काउंटर एफी डेविट में उद्धृत 20.04.2022 के कार्यकारी निर्देश) का कड़ा विरोध किया, जिसमें कुछ अपराधों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनके करने से दोषी को माफी देने की गुंजाइश से बाहर रखा गया था। कार्यकारी निर्देश (जो स्पष्ट रूप से "एक महिला की हत्या" में शामिल एक कैदी की रिहाई को प्रतिबंधित करता है), यह तर्क दिया गया था-न केवल उसके 25 साल के कारावास के पूरा होने के बाद आया, बल्कि किसी भी मामले में वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याची को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत एक दोषी की सुरक्षा को देखते हुए माफी के लिए विचार करने का कानूनी अधिकार था; इस कानूनी अधिकार की गारंटी जेल अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा दी गई थी।

6 जी. ओ. (सुश्री) नहीं। 116/2022 घर दिनांकित 14.06.2022।

513

जोसफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 514

10. संबंधित जेलों से प्राप्त जवाबों (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत) पर भरोसा करते हुए, जिसमें याची को रखा गया है-वकील ने प्रदर्शित किया कि एक महिला की हत्या में शामिल कुल 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था। हालाँकि, सलाहकार बोर्ड द्वारा उनके सुधार पर विस्तृत टिप्पणियों के साथ तीन बार सिफारिश किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अपने आदेशों में बिना कोई कारण बताए उनकी समय से पहले रिहाई के मामले को खारिज कर दिया था। यह तर्क दिया गया था कि इन आदेशों को दरकिनार करने के लिए यह आधार था।

11. अंत में, वकील ने प्रत्यर्थी राज्य द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा किया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि जेल सलाहकार बोर्ड ने याची, जो 67 वर्ष की आयु का है, को मेहनती, अनुशासित और सुधार करने वाला पाया था, और उसकी समय से पहले रिहाई के लिए प्रार्थना की।

12. अपनी दलीलों को पूरा करने के लिए, वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया, जिनमें हरियाणा राज्य बनाम जगदीश 7, मारु शामिल हैं।

राम, बनाम भारत संघ 8, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बनाम सुभाष चंद्र यादव 9, हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह 10, और राज्य बनाम एच. निलोफर निशा 11।

13. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि याची छूट पर रिहा होने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, और रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थना-इस अदालत द्वारा सरकार को उसे रिहा करने के निर्देश के लिए-बस विचारणीय नहीं थी।

14. वकील ने तर्क दिया कि माफी का अनुदान पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेक पर है, और दया का कार्य है, जो अच्छे आचरण और कारावास की अवधि के कारण दिया जाता है। यह एक अक्षम्य अधिकार नहीं है; बल्कि दोषी को केवल माफी के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, जो वह वर्तमान मामले में था। हालाँकि, यह निर्णय कि क्या छूट दी जानी चाहिए, विवेक का प्रयोग करने का एक कार्य था जो पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता था।

7 [2010] 3 एससीआर 716 8 [1981] 1 एससीआर 1196 9 [1988] 3 एससीआर 62 10 [2007] 11 एससीआर 932 11 (2020) 14 एससीसी 161

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

15. श्री गुप्ता ने अपराध की प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित किया-कि यह पूर्व नियोजित और डकैती के साथ निर्मम हत्या थी। यह तर्क दिया गया कि एक निर्दोष युवा महिला पर उस व्यक्ति द्वारा हमला किया गया जिस पर उसने भरोसा किया था, उसके बहनोई ने भी कम नहीं, जो उसका सामान लूटने के लिए आगे बढ़े और उसे इस तरह से भयानक तरीके से मार डाला, जिसने समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया। श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि ये कारक, जो निस्संदेह सजा सुनाने वाली अदालत (जिसने मृत्युन्यायालय नहीं दिया) पर भारी हैं, उन्हें अपने विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करने के लिए छूट देने वाले राज्य प्राधिकरण पर भी विचार करना चाहिए।

16. राज्य के वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया

इस न्यायालय को राजी करना-रामदास अठावले बनाम भारत संघ 12, भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण 13, हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह (ऊपर), स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य 14, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह 15 और राजन बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग 16।

विश्लेषण और निष्कर्ष

ए. लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान, नियम आदि।

17. त्रावणकोर-कोचीन जेल अधिनियम 06.06.1950 पर लागू हुआ। धारा 3 (5) और 59 (4) के आधार पर, राज्य सरकार ने 26.07.1958 पर 1958 के नियम बनाए। केरल कारागार और सुधारात्मक सेवा (प्रबंधन) अधिनियम, 2010 [इसके बाद '2010 अधिनियम'] 12/14.05.2010 पर लागू हुआ। इस अधिनियम (बचत खंड) की धारा 102 (2) के आधार पर 1958 के नियम नए नियमों (यानी 2014 के नियम) के शुरू होने तक जारी रहने थे। 14.06.2022 पर, समय से पहले रिहाई पर सामान्य दिशानिर्देशों वाला एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें कैदियों को इस तरह वर्गीकृत किया गया था कि जिन लोगों ने कुछ अपराध किए थे, उन्हें समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता था, जबकि अन्य पर 25 साल

बाद ही विचार किया जा सकता था। इस सरकारी आदेश में 20.04.2022 दिनांकित एक कार्यकारी निर्देश भी शामिल किया गया था जिसमें "एक महिला की हत्या" में शामिल लोगों को शामिल नहीं किया गया था।

12 [2010] 3 एससीआर 1059 13 [2015] 14 एससीआर 613 14 [2008] 11 एससीआर 93
15 [1976] सप.1 एससीआर 552 16 [2019] 6 एससीआर 1035 515

जोसफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 516

अन्य अपराधों के बीच, समय से पहले रिहाई के अनुदान से। सी. आर. पी. सी. की धारा 433-ए, इस हद तक भी लागू होती है कि यह वैधानिक छूट के विकल्प को तब तक बंद कर देती है जब तक कि दोषी, जिसे आजीवन कारावास (या परिवर्तित मौत की सजा) द्वारा दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, 14 साल के वास्तविक कारावास की सजा काट चुका है।

18. 2010 के अधिनियम की धारा 77 17 राज्य सरकार को या तो स्वतः या एक सलाहकार समिति की सिफारिश पर, निर्धारित नियमों के अनुसार बेहतर सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य से अच्छे व्यवहार वाले, लंबे समय तक दोषी ठहराए गए कैदियों को समय से पहले रिहा करने का अधिकार देती है। 2014 के नियमों के नियम 462 से 468 में दोषियों को समय से पहले रिहा करने पर विचार करते समय सलाहकार समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। जब भी कोई कैदी 14 साल का वास्तविक कारावास पूरा करता है, तो वह समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने के योग्य हो जाता है [संदर्भ: नियम 464 (iv) 18]। सलाहकार समिति/बोर्ड उनके मामले पर विस्तार से विचार करता है, और राज्य सरकार को, जो 2014 के नियमों के नियम 468 के तहत सशक्त है, उक्त सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सिफारिशें करता है। 19. हरियाणा राज्य बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का एक पठन।

जगदीश 19, जिसका अनुसरण हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार 20 में किया गया था

कानून की स्थिति स्पष्ट है: दोषसिद्धि की तारीख को प्रचलित छूट नीति, किसी दिए गए मामले में लागू की जानी है, और यदि विचार के दिन अधिक उदार नीति मौजूद है, तो बाद वाली नीति लागू होगी। इस दृष्टिकोण का हाल ही में इस न्यायालय ने राजो बनाम बिहार राज्य 21 में भी पालन किया था।

17 "77. समयपूर्व रिलीज।- (1) अच्छा व्यवहार करने वाले, लंबे समय तक दोषी ठहराए गए कैदियों को उनके सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य से सरकार द्वारा या तो स्वतः या एक सलाहकार समिति की सिफारिशों पर समय से पहले रिहा किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अनुसार गठित सलाहकार समिति के पास वे शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो निर्धारित किए जाएं।

18 2014 के नियमों के नियम 464 के उपखंड (iv) के अनुसार, सलाहकार बोर्ड को 10 साल के कारावास (छूट के साथ) के पूरा होने पर आजीवन कैदियों पर विचार करना है, जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए

द्वारा बाहर नहीं किया जाता है, इस मामले में उन्हें 14 साल के वास्तविक कारावास के पूरा होने के बाद विचार किया जाना है।

19 [2010] 3 एस. सी. आर. 716 [पैरा 35,43]। 20 (2021) 9 एससीसी 292 [पैरा 16]।

21 रिट याचिका (सी. आर. एल.) में दिनांकित 25.08.2023 निर्णय। नं. 252/2023 [पैरा 23]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

20. इस न्यायालय की एक निर्णायक पीठ, मारु राम बनाम भारत संघ 22 मामले में, न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के आवेदन पर विचार करते समय, जब निचली विचारण न्यायालय ने इसे शामिल करने से पहले एक आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन धारा 433-ए के लागू होने के बाद अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अभिनिर्धारित किया:

“[...] जब किसी व्यक्ति को अपील में दोषी ठहराया जाता है, तो यह इस प्रकार है कि अपीलीय न्यायालय ने मूल न्यायालय के स्थान पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और अपराध, दोषसिद्धि और सजा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और इसका प्रभाव विचारण न्यायालय के निर्णय की तारीख से पूर्वव्यापी होगा। अपीलीय दोषसिद्धि का संबंध निचली अदालत के फैसले की तारीख से होना चाहिए और इसे प्रतिस्थापित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, भले ही अपीलीय न्यायालय धारा 433-ए के लागू होने से पहले दिए गए पहले के बरी होने के फैसले को उलट देता है, लेकिन धारा 433-ए के लागू होने के बाद अपील की अनुमति देता है और आरोपी को दोषी ठहराता है, ऐसे व्यक्ति भी धारा 433-ए से पहले प्रचलित माफी प्रणाली के लाभ के हकदार होंगे, जिस आधार पर हमने समझाया है। अपील मूल निर्णय के प्रतिस्थापन के रूप में एक अपीलीय निर्णय की निरंतरता है।”

21. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, दोषसिद्धि की तारीख, हालांकि वास्तव में 06.01.1998-यानी उच्च न्यायालय के फैसले के दिन, निचली विचारण न्यायालय के फैसले की तारीख से संबंधित मानी जाती है, जो 23.03.1996 पर दिया गया था। इस तारीख को (जैसा कि 1998 में भी था जब उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था), 1958 के नियम लागू थे।

22. बहुत हद तक 2014 के नियमों की तरह [नियम 464 (iv) देखें], 1958 के नियम इसी तरह 14 साल पूरे करने वाले दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने का अधिकार देते हैं। नियम 545 ए नीचे दिया गया है:

“545 ए. '14-वर्षीय नियम'।- जिन कैदियों की कुल सजा 20 वर्ष से अधिक है, उनके मामलों को नियम 545 के तहत निर्दिष्ट रिकॉर्ड के साथ सरकार के विशेष आदेशों के लिए उनकी समय

से पहले रिहाई या प्रत्येक मामले में छूट सहित 14 साल की सजा पूरी करने के लिए किया जाएगा।

****** “बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जिसके लिए मृत्यु एक है -

22 [1981] 1 एससीआर 1196 [पैरा 20]।

517

जोसफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भारत, जे.] 518 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

कानून द्वारा प्रदत्त दंड, या जहां किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 के तहत मृत्युदंड की सजा दी गई है, ऐसे व्यक्तियों को जेल से रिहा करने के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उन्होंने कम से कम 14 साल का कारावास नहीं बिताया हो।”

23. जब रिहाई की तारीख की बात आती है, तो 1958 के नियमों में भी विभिन्न प्रावधानों में, x 20 वर्ष, आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी के लिए मानित सजा होगी:

“216. रिलीज की तारीख जब दो या दो से अधिक वाक्य लगातार चलते हैं।-

(1) रिहाई की सामान्य तिथि की गणना के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आजीवन कारावास या कुल मिलाकर 20 साल से अधिक के कारावास या कुल मिलाकर 20 साल से अधिक के कारावास की सजा पाए सभी कैदियों की सजा को 20 साल के कारावास की सजा माना जाएगा।

244. दोषियों द्वारा पहने जाने वाले टिकट।- [...]

(2)(ख) स्वास्थ्य या जीवन को दर्शाने वाले तारों जैसे कोई अन्य विवरण उस पर दर्ज नहीं किए जाएंगे, और टिकट के पीछे कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा। आजीवन कारावास की सजा के तहत दोषसिद्धि के लिए रिहाई की तारीख को सजा की तारीख से 20 साल के रूप में लिया जाएगा। वैकल्पिक कारावास की अवधि वाले दोषी के मामले में, रिहाई की वैकल्पिक तिथि भी दिखाई जानी चाहिए।

299. इन नियमों में परिभाषाएँ।- [...]

(ग) आजीवन कारावास या कुल मिलाकर बीस वर्ष से अधिक कारावास या कुल मिलाकर बीस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा पाए सभी कैदियों की सजा इन नियमों के उद्देश्य से बीस वर्ष के कारावास की सजा मानी जाएगी।”

'मानित' आजीवन कारावास की सजा के संबंध में समान प्रावधान 2014 के नियमों के नियम 377 23 में पाया जा सकता है।

23 “377. दोषसिद्धि अवधि का निर्धारण-(1) आजीवन कारावास या कुल मिलाकर बीस वर्ष से अधिक के कारावास या कुल मिलाकर बीस वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा पाए सभी कैदियों की सजा, छूट नियमों के उद्देश्य से, 20 वर्ष के कारावास की सजा मानी जाएगी।

B. वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में कानून का विश्लेषण करना

24. 2010 के अधिनियम की धारा 99, राज्य सरकार को अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने का अधिकार देती है, और उपखंड (XXXII) प्राधिकरण से विशिष्ट रूप से संबंधित है जो धारा 77 के तहत कैदियों की समय से पहले रिहाई की सिफारिश कर सकता है। राज्य सरकार ने बड़ी मेहनत से इन नियमों को तैयार किया है। 2014 के नियमों के नियम 462 के अनुसार, कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक जेल में जेल सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। इन बोर्डों की संरचना में शामिल हैं-अध्यक्ष के रूप में जेल और सुधार सेवा महानिदेशक, सदस्य सचिव के रूप में जेल अधीक्षक, और जिला कलेक्टर, जिला और सत्र न्यायाधीश, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस प्रमुख, जिला परिवीक्षा अधिकारी, और सरकार द्वारा नियुक्त तीन गैर-आधिकारिक सदस्य-सदस्यों के रूप में।

25. संबंधित हितधारकों से युक्त इस विविध बोर्ड ने याचिकाकर्ता के मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखने के बाद, तीन अलग-अलग अवसरों-10.01.2017, 26.02.2020, और 07.03.2022 पर उनकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश की। फिर भी, राज्य सरकार ने बिना कोई कारण बताए-जो शायद अनुशंसित प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर सकती थी-केवल तीनों बार (06.07.2019, 22.04.2021, और 01.09.2022) इसे अस्वीकार कर दिया। यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

26. यह कि किसी सजा का निष्पादन, राज्य/कार्यपालिका का एकमात्र विशेषाधिकार है, जो संवैधानिक रूप से (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 और 72) और सांविधिक रूप से (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और राज्य अधिनियम) दिए गए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, वह प्रश्नगत नहीं है। हालाँकि, सभी शक्तियों की तरह-इसका प्रयोग निष्पक्ष, यथोचित और मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। 24 27. जबकि केरल राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांक 04.06.2022 को सीधे चुनौती नहीं दी गई है, यह इस अदालत की सुविचारित राय है कि यह

(2) छूट की गणना के लिए अधिनियम की धारा 72 और उप-धारा (1) के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा।”

24 छूट और सजा के संदर्भ में, देखें -हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह

[2000] 1 एस. सी. आर. 698; संगीत बनाम हरियाणा राज्य [2012] 13 एस. सी. आर. 85; भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण [2015] 14 एस. सी. आर. 613; राजन बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग [2019] 6 एस. सी. आर. 1035; राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2022] 4 एस. सी. आर. 1103।

जोसफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भारत, जे.] 520 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023]
12 एस. सी. आर.

टिप्पणी के लायक है, और सावधानी का एक नोट। सरकारी आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

- “I. उन कैदियों की श्रेणी जो समय से पहले रिहाई के पात्र नहीं हैं। 1. जिन व्यक्तियों को राज्य की सुरक्षा के खिलाफ अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
2. व्यक्ति जिसे पॉक्सो अधिनियम 2012 के साथ या उसके बिना 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के बलात्कार के साथ हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
3. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति।
4. जिन मामलों में न्यायालय स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि कैदी को विशेष छूट या माफी नहीं दी जाएगी, उनमें शामिल व्यक्ति। 5. अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए और सजा पाए व्यक्ति।

II. सभी प्रकार की छूट सहित 25 साल की सजा पूरी करने के बाद ही पात्र कैदियों की श्रेणी।

1. बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षण के तहत किसी भी अपराध से जुड़ी हत्या, दहेज के लिए हत्या, 14 साल से कम उम्र के बच्चे की हत्या, कई हत्या, जेल के अंदर दोषी ठहराए जाने के बाद हत्या, पैरोल के दौरान हत्या, आतंकवादी घटना में हत्या, तस्करी अभियान में हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या, डकैती के साथ हत्या और 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार।
2. गैंगस्टर्स, अनुबंध हत्यारों, तस्करो, नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों को हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
3. जिन दोषियों की मौत की सजा को भारत के माननीय राष्ट्रपति या माननीय राज्यपाल द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है। निम्नलिखित आयु वर्ग और पूर्ण सजा वाले कैदी और परिवीक्षा अधिकारी से अनुकूल रिपोर्ट इस श्रेणी के तहत पात्र हैं:-

(क) ऐसे कैदी जिनकी आयु 55 वर्ष हो गई है और जिन्होंने छूट सहित 25 वर्ष की सजा पूरी कर ली है; या

(ख) वे कैदी जिन्होंने वास्तविक सजा के 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। III. छूट सहित 20 साल की सजा के बाद पात्र कैदियों की श्रेणी

सभी कैदी जो श्रेणी I और II के तहत नहीं आते हैं, वे 20 साल की सजा के बाद समय से पहले रिहाई के लिए पात्र होंगे, जिसमें उनकी उम्र की परवाह किए बिना माफी भी शामिल है, लेकिन निम्नलिखित शर्तों पर।

[...]"

इसके अलावा, समिति द्वारा अनुशंसित कुछ अन्य दोषियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने

“निम्नलिखित श्रेणी के कैदियों को छोड़कर प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया:

1. सबसे क्रूर हत्या में शामिल व्यक्ति।
2. जिन लोगों ने महिलाओं और बच्चों की हत्या की, जिन लोगों ने बलात्कार के साथ हत्या की।
3. मानसिक बीमारी के लिए इलाज करा रहे कैदियों में, वे कैदी जिनके रिश्तेदार उन्हें लेने के लिए अनिच्छुक हैं।

इस प्रकार, सामान्य दिशानिर्देशों में शामिल करते हुए, तीन श्रेणियों को बाहर कर दिया गया क्योंकि वे पहले के कार्यकारी निर्देश दिनांक 20.04.2022 में दिखाई दिए थे।

28. बनाए गए अधिनियम और नियमों के ऊपर और ऊपर एक नीतिगत निर्देश, या दिशानिर्देश जारी करना (जहां बाद वाला पूर्व का हिस्सा है), और जो वे शामिल करते हैं उसे कमजोर करना, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से एक कार्यकारी नीति के माध्यम से, छूट के अनुदान के दायरे से कुछ ऑफ एनस का खाली बहिष्कार न केवल मनमाना है, बल्कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से चलने वाले सुधार के आदर्शों को अपने सिर पर बदल देता है। इस न्यायालय के कई निर्णयों ने सुधार और पुनर्वास के न्यायालयात्मक लक्ष्य पर विस्तार से बताया है, जो प्रतिशोध के बजाय हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है। कार्यपालिका के विवेक का मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह के कार्यकारी निर्देश/दिशानिर्देश को लागू करने का प्रभाव 521 होगा।

जोसेफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 522

कि नियमित रूप से, एक दीर्घकालिक दोषी द्वारा की गई किसी भी प्रगति को व्यर्थ कर दिया जाएगा, जिससे वे निराश महसूस करेंगे, और अनिश्चित काल के कारावास की निंदा की जाएगी। हालांकि सजा सुनाने वाली अदालतें, श्रीहरण (उपरोक्त) में इस अदालत के बहुमत के फैसले के आलोक में, अब उन अपराधों के लिए (14 या 20 साल से अधिक) सजा दे सकती हैं जो विशेष रूप से जघन्य हैं, लेकिन 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' (मृत्युदंड की गारंटी) के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, राज्य सरकार-विशेष रूप से कार्यकारी निर्देश के माध्यम से, ऐसे अपराधों के लिए ऐसी भूमिका नहीं निभा सकती है, जो वह मानते हैं।

29. यह प्रशासनिक कानून का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रस्ताव है कि पूर्ण कानून या वैधानिक नियमों द्वारा व्यापक रूप से प्रदत्त विवेकाधिकार को हल्के में नहीं बांधा जा सकता है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है।

समय। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और ए. एन. आर. बनाम मोहम्मद। इस्माइल और ओआरएस। 25, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“यह कहा जा सकता है कि वैधानिक विवेकाधिकार को स्व-निर्मित नियमों या नीतियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यह एक ऐसे प्राधिकरण के लिए खुला है जिसे विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए मानदंडों या नियमों को निर्धारित करने के लिए विवेकाधिकार सौंपा गया है, हालाँकि, यह स्वयं को उस विवेकाधिकार से इनकार नहीं कर सकता है जिसे कानून व्यक्तिगत मामलों में प्रयोग करने की आवश्यकता रखता है।” 30. इसी तरह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे रोक। बोर्ड और ओआरएस. वी.

के. श्याम कुमार और अन्य। 26 इस न्यायालय ने इस मुद्दे को निम्नलिखित तरीके से समझाया:

“न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में अवैधता का अर्थ है कि निर्णय निर्माता को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्तियों को नियंत्रित करता है और उसे प्रभाव देना चाहिए। अधिकार से बाहर काम करना, कानून की त्रुटियाँ और/या तथ्य, कठिन परिस्थितियाँ, अनुचित उद्देश्य, प्रासंगिक और अप्रासंगिक कारक, दुर्भावना से काम करना, विवेक को बांधना, अनधिकृत प्रत्यायोजन, कार्य करने में विफलता आदि जैसे आधार “अवैधता” शीर्षक के तहत आते हैं। प्रक्रियात्मक अनुचितता अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता के कारण हो सकती है जैसे कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, जैसे कि ऑडी अल्टरम पार्टेम, पूर्वाग्रह का अभाव, निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य, वैध अपेक्षाएं, कारण देने में विफलता आदि।”

25 [1991] 2 एससीआर 274 26 [2010] 6 एससीआर 291

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

31. संविधान ने अनुच्छेद 72 और 162 के तहत कार्यपालिका को छूट, परिवर्तन आदि जैसे मामलों के संबंध में जो अक्षांश दिया है, उसे दिशानिर्देशों के रूप में बंद नहीं किया जा सकता है।

32. हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह 27 में इस अदालत की टिप्पणियाँ

यहाँ भी प्रासंगिक हैं:

“38. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए माफी के लिए विचार किए जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिए।

इस तरह का कानूनी अधिकार न केवल जेल अधिनियम से बल्कि उसके तहत बनाए गए नियमों से भी निकलता है।³⁹ अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कोई भी दिशानिर्देश जिसमें कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, केवल सलाहकार प्रकृति के हैं। उनके पास कानून का बल नहीं हो सकता है। वे विधायी अधिनियम और वैधानिक नियमों के अधीन हैं।”

(जोर दिया गया) 33। वर्गीकरण-एक बेहतर शब्द का उपयोग करने के लिए, दोषियों को टाइपकास्ट करना, उन दिशानिर्देशों के माध्यम से जो दूर के अतीत में किए गए उनके अपराध के आधार पर, प्रत्येक व्यक्तिगत दोषी की सुधारात्मक क्षमता की अनदेखी करने का वास्तविक खतरा हो सकता है। प्रारंभिक बिंदु के रूप में, दोषियों के प्रकारों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर समूहीकृत करना न्यायसंगत हो सकता है। हालाँकि, भारत में जेल कानून-जिन्हें अनुच्छेद 72 और 161 के सहपठित पढ़ा जाता है-एक मजबूत अंतर्निहित सुधारात्मक उद्देश्य को समाहित करते हैं। एक दिशानिर्देश का व्यावहारिक प्रभाव, जो पूरी तरह से 20 या 25 वर्ष से अधिक की सेवा देने वाले एक दोषी द्वारा समय से पहले रिहाई के अनुरोध पर विचार करने पर रोक लगाता है।

दूर के अतीत में किए गए अपराध की प्रकृति पर, कुचलना होगा

ऐसे व्यक्ति से जीवन शक्ति, पूरी तरह से। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक 19 या 20 वर्षीय व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो सूची में शामिल है जो समय से पहले रिहाई को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, इसका मतलब यह होगा कि ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वतंत्रता नहीं देखेगा, और जेल की दीवारों के भीतर ही मर जाएगा। वर्षों पहले अपराध करने वाले व्यक्ति को कैद में रखने की एक विशिष्टता है जो उस समय से पूरी तरह से बदल गया होगा। बहुत लंबे समय तक सजा काट रहे कई लोगों की यह स्थिति है। उनके पास हो सकता है

27 (2007) 13 एससीसी 606 523

जोसेफ बनाम केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] 524

युवा व्यक्तियों के रूप में किसी को मार डाला (या कुछ कम गंभीर काम किया, जैसे कि मादक पदार्थ से संबंधित मादक पदार्थ लेना या अन्य अहिंसक अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काटना) और 20 या अधिक वर्षों के बाद जेल में रहते हैं। निरंतर सजा की नैतिकता के बावजूद, कोई भी इसकी तर्कसंगतता पर सवाल उठा सकता है। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करना जारी रखने से क्या हासिल होता है जो अपने किए गए गलत काम को पहचानता है, जो अब इसके साथ अपनी पहचान नहीं रखता है, और जो उस व्यक्ति से बहुत कम मिलता-जुलता है जो वे वर्षों पहले थे? यह कहना लुभावना है कि वे अब एक ही व्यक्ति नहीं हैं। फिर भी, दिशानिर्देशों का आग्रह, स्पष्ट रूप से, इसके द्वारा खींची गई लाल रेखाओं से परे नहीं देखना और जेल के अच्छे व्यवहार के वास्तविक प्रभाव और अन्य प्रासंगिक कारकों (यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को समाज को नुकसान पहुंचाने की संभावना से मुक्त कर दिया गया है) पर विचार करने से इनकार करना जारी रखना, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

बहुत लंबे समय तक कैद में रहने वाले कैदियों को समय से पहले रिहा करने की राहत को छोड़कर, न केवल उनकी भावना को कुचलता है, और निराशा पैदा करता है, बल्कि यह कठोर और अक्षम्य होने के समाज के संकल्प को दर्शाता है। अच्छे आचरण के लिए एक कैदी को पुरस्कृत करने का विचार पूरी तरह से नकार दिया जाता है।

34. याचिकाकर्ता के मामले में, 1958 के नियम स्पष्ट हैं-एक आजीवन कारावास, जिसे 20 साल का कारावास माना जाता है। इसके बाद कैदी समय से पहले रिहा होने का हकदार होता है। 28 एन. एच. आर. सी. द्वारा याची के वकील द्वारा हमें जारी किए गए दिशा-निर्देश भी विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं-25 साल की सजा काटने के बाद (यहां तक कि जघन्य अपराधों में भी) रिहाई को अनिवार्य करना। इस मोड़ पर, याची को, जो पहले ही 26 वर्षों से अधिक कारावास (और छूट के साथ 35 वर्षों से अधिक की सजा) से गुजर चुका है, हमारे सामने सलाहकार बोर्ड के समक्ष फिर से विचार करने के लिए, और उसके बाद, समय से पहले रिहाई के लिए राज्य सरकार को पुनर्निर्देशित करना-एक क्रूर परिणाम होगा, जैसे कि प्रक्रिया के नाम पर एक उग्र अपराध के लिए केवल एक बचाव दिया जाता है। कानून के शासन और निष्पक्षता के विचार की भव्य दृष्टि तब प्रक्रिया की वेदी पर बह जाती है-जिसे इस न्यायालय ने बार-बार देखा है।

"न्याय की दासी" माना जाता है।

35. 2014 के नियमों के नियम 376 में निर्धारित किया गया है कि कैदियों को जेल में शांति और अच्छा व्यवहार रखने के लिए छूट दी जाएगी। राज्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, याची ने 8 वर्षों से अधिक की कमाई की है।

28 आपराधिक अपील सं. 276-278/2010 में इस अदालत का दिनांकित 11.10.2018 आदेश भी देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

क्षमा, इस प्रकार जेल में अपने अच्छे आचरण का प्रदर्शन। जेल सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में चर्चा भी सकारात्मक और आश्चस्त है कि वह मेहनती, अनुशासित और एक सुधार कैदी है। इसलिए, न्याय के हित में, इस न्यायालय की राय है कि याची को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का निर्देश देना उचित होगा। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

36. इस प्रकार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।

निधि जैन

